



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 मार्च, 2001/9 चैत्र, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 मार्च, 2001

संख्या: 1-17/2001-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत "पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्यांक-2) जो

आज दिनांक 30 मार्च 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनाएं राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 2.

पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना), 1949 द्वारा यथा लागू, पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के वावचरें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) संक्षिप्त नाम । ऐक्ट, 2001 है ।

1966 का

31

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में लागू पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 61 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 61-A
का अंतःस्था-
पन ।

“61-A. *Composition of certain offences.*—(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 61, any offence, whether committed before or after the commencement of the Punjab Excise (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2001, relating to the imports, exports, transportation or possession upto 60 litres of Lahan or upto 18 bulk litres of liquor, may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the Judicial Magistrate of the 1st Class, for an amount which shall not be less than one thousand rupees but shall not exceed twenty five thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence :

Provided that if a person commits an offence specified in sub-section (1), for more than three times, the same shall not be compounded.

(3) When a case has been compounded under sub-section (1), the Judicial Magistrate of the 1st Class may make such order as he thinks fit for the disposal of the case property.”

धारा 65 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 में शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और चिन्ह, "in case (a) with fine which may extend to two hundred rupees, and in case (b) or in case (c) with fine which may extend to five hundred rupees", के स्थान पर "with fine which may extend to twenty five thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और विलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्त है, और यह अधिनियम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन, हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 88 के उपबन्धों के फलस्वरूप भी प्रवृत्त है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 61, मादक द्रव्यों के विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जे इत्यादि के लिए शास्ति का उपबन्ध करती है। वर्तमानतः छोटे-छोटे आबकारी मामलों के शमन के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। इस समय छोटे-छोटे आबकारी मामले अधिकांश संख्या में या तो अनवेपक एजेंसियों के पास लम्बित हैं या फिर विभिन्न न्यायालयों में निपटारे के लिए लम्बित हैं। इन मामलों के लम्बित रहने को कम करने के लिए यह विनिश्चित किया गया है कि 60 लीटर लाहन तक के या 18 लीटर की थोक मात्रा तक के मद के किए गए आयात, निर्यात, परिवहन या कब्जे के बारे में अपराधों को, चाहे वे प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के पूर्व किए गए हों या बाद में किए गए हों, शमनीय बनाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अभियोजन एजेंसियां और न्यायालय अन्य गम्भीर प्रकृति के मामलों में अधिक समय दे सकने में समर्थ होंगे। इसलिए, नई धारा 61-A अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी या उसके कर्मचारी द्वारा किए गए कतिपय कृत्यों के लिए धारा 65 में उपबंधित शास्ति, केवल नाम मात्र है जिसकी वृद्धि की जानी भी अपेक्षित है ताकि इस धारा के उपबन्धों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। इसलिए, यह विनिश्चित किया गया है कि शास्ति 5,000 (पांच हजार) रुपये से कम नहीं होगी और जो 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये तक बढ़ाई जा सकेगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रवीण शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

क्षिप्रतः :

..... 2001.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में नए कर/शुल्क उद्ग्रहीत करने का प्रस्ताव नहीं है। विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित किए जाने पर, विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा प्रवृत्त किए जाएंगे। अतः राज्य सरकार को न तो कोई अतिरिक्त आय होगी और न ही कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्बलित होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

पंजाब एक्साइज (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त; और प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा यथा लागू पंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रवीण शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)।

शिमला :

..... 2001.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No 2 of 2001.

**THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT
BILL, 2001**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966); and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Punjab Excise (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2001.

[Short title]

2. After section 61 of the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966; and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 (hereinafter referred to as 'principal Act'), the following new section shall be inserted, namely :—

Insertion
of section
61-A.

“61-A. *Composition of certain offences.*—(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 61, any offence, whether committed before or after the commencement of the Punjab Excise (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2001, relating to the imports, exports, transportation or possession upto 60 litres of lagan or upto 18 bulk litres of liquor may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the Judicial Magistrate of the 1st Class, for an amount which shall not be less than one thousand rupees but shall not exceed twenty five thousand rupees.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence :

Provided that if a person commits an offence specified in sub-section (1) for more than three times, the same shall not be compounded.

(3) When a case has been compounded under sub-section (1), the Judicial Magistrate of the 1st Class may make such order as he thinks fit for the disposal of the case property.”

Amendment
of section
65.

3. In section 65 of the principal Act, for the words, brackets, letters and signs "in case (a) with fine which may extend to two hundred rupees, and in case (b) or in case (c) with fine which may extend to five hundred rupees", the words "with fine which may extend to twenty five thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act No. 1 of 1914) as in force in the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966, as applied *vide* the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949 ; and also as in force by virtue of the provisions of section 88 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (Central Act No. 31 of 1966) in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the said Central Act. Section 61 of the Act *ibid* provides for penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession etc. of intoxicants. There is presently no provision in the Act *ibid* for composition of petty excise cases. There are large number of petty excise cases either pending with the investigating agencies or pending in the various courts for disposal. In order to reduce the pendency of these cases, it has been decided that offences relating to the imports, exports, transportation or possession upto 60 litres of lagan or upto 18 bulk litres of liquor, whether committed before or after the commencement of the proposed amending Act should be made compoundable. As a result of this, the prosecuting agencies and the courts will be able to devote more time to the other cases of serious nature. As such, a new section 61-A has been proposed to be inserted. Further the penalty provided in section 65 for certain acts by licensee or his servant is very nominal which is also required to be enhanced so as to make the provisions of this section more stringent. As such, it has been decided that the penalty should not be less than five thousand rupees and may be extended to twenty five thousand rupees.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA :

The....., 2001.

PARVEEN SHARMA,
Minister-in-Charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill does not propose to levy fresh taxes/duties. The provisions of the Bill, when enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there will be no extra income to the State Government and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE PUNJAB EXCISE (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2001

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as in force in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966) ; and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 vide the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order, 1949.

PARVEEN SHARMA,
Minister-in-Charge.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2001.

FOURTH EDITION, 1999, PUBLISHED BY THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH